भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 982
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

नई शिक्षा नीति की समीक्षा

†982. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा शुरू कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों के लिए एनईपी 2020 की समीक्षा में शामिल की गई विकास संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि हां, तो एनईपी 2020 की समीक्षा में लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा दिनांक 29.07.2020 को ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, शहरी स्थानीय निकायों, जिलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, माननीय संसद सदस्यों, आम जनता आदि सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद की गई है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ सिद्धांतों और कार्यप्रणाली का उल्लेख है, जिसे कई निकायों द्वारा समन्वित और व्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित करना होगा। इसलिए, इस नीति के कार्यान्वयन का नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा से संबंधित अन्य मंत्रालयों, राज्य शिक्षा विभागों, बोर्डों, एनटीए, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक निकायों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों सहित विभिन्न निकायों द्वारा किया जाता है। एनईपी में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सावधानीपूर्वक योजना बनाने, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन का भी प्रावधान है।

तदनुसार, केंद्र सरकार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के कार्यान्वयन के लिए कई पहलें की हैं। एनईपी कार्यान्वयन के लिए प्रगति

की समीक्षा और नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षिक संस्थानों, अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा जून 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन; जून 2022 में आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 और 2023 आदि में की गई।

एनईपी 2020 की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूली शिक्षा परिवर्तनों में आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा की शुरुआत; मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ध्यान; सभी स्तरों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग; डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा); बहु-विषयक वातावरण में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण; एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के सृजन के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर); "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-साक्षरों आदि को लक्षित करता है, आदि शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न परिवर्तनकारी बदलावों में अत्यावश्यक लोचनीयता प्रदान करना, विषयों के रचनात्मक संयोजन की अनुमति देना, एकाधिक कार्यक्रम प्रदान करना, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, क्रेडिट अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), एकाधिक प्रवेश/निकास, भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम और पुस्तकें/पाठ्य सामग्री प्रदान करना; जेईई, नीट, सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित करना; शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रशासन और शासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग; शिक्षार्थियों को स्वयम प्लेटफॉर्म से 40% तक क्रेडिट पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने की अनुमति देना; उद्योग और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने हेतु इंटर्नशिप के लिए तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विकसित करने हेतु उद्योग अकादमिक सहयोग, उद्योग-अनुकूल पाठ्यक्रम संचालित करना; विदेश और भारत में क्रमशः भारतीय और विदेशी एचईआई के परिसरों की स्थापना को बढ़ावा देना; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि; शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करना आदि शामिल है।

एनईपी 2020 के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है, जिससे हितधारकों से सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों के दौरान, विचारों का जोरदार आदान-प्रदान हुआ है, राज्यवार पहलों पर चर्चा हुई है, विभिन्न राज्यों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया है, साथ ही एनईपी 2020 को लागू करने की चुनौतियों और रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया है। इन प्रयासों से नीति के कार्यान्वयन के लिए एक समन्वित और व्यवस्थित दृष्टिकोण सुविधाजनक बना है।

*****